आज का मौसम

अधिकतम 33° C
न्यूनतम 28° C
सूर्य अस्त (आज) 7:24
सूर्य उदय (कल) 5:36

दैनिक समाचार पत्र

जीत समाचार

जीत सच्ची खबर की

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश

अनमोल वचन

"अगर धन दूसरों की भलाई करने में काम आए, तो इसका कुछ मूल्य है अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जल्दी छुटकारा मिल जाए, उतना बेहतर है।"

वर्ष : 13 | अंक : 304 | मूल्य : 2 रू | पृष्ठ : 8 | बुधवार 22 जुलाई 2026 | RNI NO : PUNHIN/2013/60106 | www.zeetsamachar.com

संक्षिप्त न्यूज़

छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में राहुल-प्रियंका का प्रदर्शन, पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग

नई दिल्ली। छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है। सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा और कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के निकट धरना देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की।

प्रधानमंत्री आवास 7, लोक कल्याण मार्ग के समीप धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं ने ष्प्रधानमंत्री इस्तीफा दोष के नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज को दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

धरने से पहले संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी अपना पद छोड़ देना चाहिए।

वहीं, प्रियंका गांधी वाद्रा ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद में इस मुद्दे पर चर्चा चाहता है, लेकिन उसे बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा। प्रियंका ने कहा कि जिन युवाओं पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, उनकी बात सुनी जानी चाहिए और इस पूरे मामले की जवाबदेही तय करते हुए शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लिया जाना चाहिए।

धरने से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचकर पुलिस कार्रवाई में घायल छात्रों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। कांग्रेस ने छात्रों के साथ एकजुटता जताते हुए कहा कि वह उनके अधिकारों और भविष्य की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी।

उधर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस लगातार सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगा रही है, जबकि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

बिहार में सीएम आवास और सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर

संवाद न्यूज एजेंसी

पटना। बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री सचिवालय और बिहार सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना सामने आई। धमकी एक ईमेल के जरिए भेजी गई, जिसके बाद पुलिस, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड में आ गईं। संवेदनशील सरकारी परिसरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 7:57 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय और बिहार भवन को एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें दावा किया गया कि अलग-अलग समय पर दो विस्फोट किए जाएंगे। ईमेल भेजने वाले ने स्वयं को 'खालिस्तान नेशनल आर्मी' से जुड़ा बताया और धमकी में हरदीप सिंह निज्जर की मौत का बदला लेने जैसी बातें लिखीं। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं।

ईमेल में कथित तौर पर दावा किया गया कि दोपहर 3:11 बजे पटना सचिवालय को निशाना बनाया जाएगा, जबकि रात 9:11 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास में विस्फोट करने की धमकी दी गई। इसके साथ ही ईमेल में कुछ अन्य गंभीर आरोप भी लगाए गए, जिनकी सत्यता की जांच की जा रही है।

धमकी मिलने के तुरंत बाद सचिवालय थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सुरक्षा के मद्देनजर सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास और आसपास के क्षेत्रों में डॉग स्क्वायड, बम निरोधक दस्ते तथा अन्य सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। पूरे परिसर की गहन तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके।

उधर, पुलिस की साइबर सेल धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच में जुट गई है। जांच एजेंसियां ईमेल के स्रोत, आईपी एड्रेस और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि ईमेल किस स्थान से भेजा गया और इसके पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री के मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। चाहे धमकी वास्तविक हो या फर्जी, ऐसी घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था की सतर्कता की परीक्षा लेती हैं। इसी कारण सुरक्षा एजेंसियां पूरी गंभीरता के साथ हर पहलू की जांच कर रही हैं।

फिलहाल जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, बोले- दोषियों पर हुई सख्त कार्रवाई, युवाओं के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़

नई दिल्ली(एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद में नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि इस प्रकरण में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई खिलवाड़ न कर सके।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामले को गंभीरता से लिया है और जांच एजेंसियों ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। उन्होंने दोहराया कि युवाओं के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि केवल कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना भी आवश्यक है। इसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग की जरूरत है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्य सरकारों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए सभी राज्यों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है, क्योंकि यह देश के करोड़ों छात्रों और उनके भविष्य से जुड़ा विषय है।

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाती रहेगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं का विश्वास बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और इस दिशा में लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

नीट पेपर लीक मामला पिछले कुछ समय से देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर संसद से लेकर सड़कों तक राजनीतिक बहस जारी है। विपक्ष सरकार पर परीक्षा प्रणाली में खामियों का आरोप लगा रहा है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं।

जीत सच्ची खबर की
जीत समाचार
www.zeetsamachar.com

दिल्ली हाईकोर्ट की सलाह: सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल किया जाए शिफ्ट, सरकार ने जताई सहमति

नई दिल्ली(एजेंसी)। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में 28 जून से अनशन पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत ने वांगचुक को बेहतर उपचार के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल स्थानांतरित करने की सलाह दी, जिस पर केंद्र सरकार ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई।

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने यह टिप्पणी सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में एकल पीठ के रविवार को दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए कहा कि यदि बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, तो उन्हें मेदांता अस्पताल स्थानांतरित किया जाना उचित होगा। इस पर सरकार की ओर से पेश पक्ष ने स्पष्ट किया कि वांगचुक को मेदांता अस्पताल शिफ्ट किए जाने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

सोनम वांगचुक पिछले 28 जून से प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। लंबे समय से जारी भूख हड़ताल के कारण उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता बढ़ी है, जिसके चलते उन्हें पहले सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

अब दिल्ली हाईकोर्ट की सलाह और सरकार की सहमति के बाद वांगचुक को बेहतर चिकित्सकीय देखभाल उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ने की संभावना है। मामले की अगली सुनवाई में अदालत स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट और उपचार की प्रगति पर भी विचार कर सकती है।

कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन: 'आप' ने शुरू की हेल्पलाइन, केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना

संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के साथ किया गया व्यवहार अंग्रेजों के शासनकाल की बर्बरता से भी बदतर है।

मंगलवार को जारी बयान में केजरीवाल ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की गई, उसने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी ने घायल प्रदर्शनकारियों और हिरासत में लिए गए छात्रों की मदद के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से घायल छात्रों और प्रदर्शनकारियों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि हिरासत में लिए गए छात्रों और उनके परिजनों को कानूनी सहायता भी प्रदान की जाएगी।

केजरीवाल ने कहा कि पार्टी के स्वयंसेवकों, डॉक्टरों और वकीलों की टीम प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि जिन्हें चिकित्सा या कानूनी सहायता की आवश्यकता है, वे हेल्पलाइन के माध्यम से संपर्क करें।

'आप' का कहना है कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए वह हर स्तर पर उनके साथ खड़ी रहेगी। वहीं, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गरमाता जा रहा है और विपक्ष केंद्र सरकार से पुलिस कार्रवाई पर जवाब मांग रहा है।

भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी, 4 से 60 वर्ष के लोगों को मिलेगा लाभ

संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। भारत ने डेंगू की रोकथाम की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए देश की पहली डेंगू वैक्सीन 'क्यूडेंगा' के विपणन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के तहत औषधि महानियंत्रक ने टाकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया द्वारा विकसित इस वैक्सीन के विपणन की अनुमति प्रदान की है।

कंपनी के अनुसार, क्यूडेंगा वैक्सीन को 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए मंजूरी दी गई है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे लगाने से पहले यह जांच कराने की आवश्यकता नहीं होगी कि व्यक्ति को पहले कभी डेंगू हुआ है या नहीं। इससे बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाने में आसानी होगी।

टाकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स के मुताबिक, यह वैक्सीन डेंगू वायरस के विभिन्न प्रकारों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित की गई है। भारत में इसकी मंजूरी को डेंगू नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि हर वर्ष देश में लाखों लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं।

40 से अधिक देशों में पहले ही मिल चुकी है मंजूरी: क्यूडेंगा वैक्सीन को भारत से पहले यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ब्राजील, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना सहित 40 से अधिक देशों में नियामक मंजूरी मिल चुकी है और कई देशों में इसका उपयोग भी किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीन डेंगू से बचाव का एक प्रभावी साधन बन सकती है, लेकिन इसके साथ-साथ मच्छरों की रोकथाम, साफ-सफाई, जलभराव रोकना और समय पर उपचार जैसे उपाय भी उतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे।

भारत में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस वैक्सीन की मंजूरी को सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। अब इसके उपलब्ध होने और टीकाकरण की प्रक्रिया को लेकर आगे की रणनीति पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए जाने की उम्मीद है।

सिक्किम सुरंग हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने जताया गहरा शोक, राहत एवं बचाव कार्य की सफलता की कामना

संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सिक्किम में सुरंग ढहने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में कहा कि सिक्किम में सुरंग हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। उन्होंने इस कठिन समय में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके दुख को सहने की शक्ति मिलने की कामना की।

राष्ट्रपति मुर्मु ने सुरंग में फंसे अन्य श्रमिकों के शीघ्र एवं सुरक्षित बचाव की प्रार्थना भी की। उन्होंने राहत और बचाव कार्य में जुटी एजेंसियों की सफलता की कामना करते हुए कहा कि सभी प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए।

इसके साथ ही राष्ट्रपति ने हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की और आशा व्यक्त की कि उन्हें समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

गौरतलब है कि सिक्किम में सुरंग ढहने की घटना के बाद राहत एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है। विभिन्न एजेंसियां मौके पर पहुंचकर मलबे में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के प्रयास में जुटी हैं। राष्ट्रपति के शोक संदेश के बाद देशभर से भी संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं।

जीत समाचार
जीत सच्ची खबर की
www.zeetsamachar.com

सम्पादकीय

दैनिक समाचार पत्र
बुधवार, 22 जुलाई 2026

डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर –

'शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।'

नीट पेपर लीक विवाद: छात्रें के गुस्से की गूंज, जंतर-मंतर बना आंदोलन का केंद्र

नई दिल्ली। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर देशभर में छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। पेपर लीक के आरोपों और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों के बीच राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र बन गया है। बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और युवा संगठन न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि मेहनत और वर्षों की तैयारी के बाद परीक्षा देने वाले लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। छात्रों ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाया जाए।

छात्रों की मांग-पारदर्शी व्यवस्था हो सुनिश्चित

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मेडिकल प्रवेश जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता से प्रतिभाशाली छात्रों का भरोसा टूटता है। छात्रों ने सरकार और जांच एजेंसियों से अपील की है कि मामले की गहराई से जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए।

जंतर-मंतर पर बढ़ी हलचल

दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगातार हो रहे प्रदर्शनों में छात्रों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें रखीं। कई छात्र संगठनों ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए परीक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई है। प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है।

सरकार और जांच एजेंसियों की नजर

नीट विवाद को लेकर जांच एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। सरकार की ओर से भी परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाने की बात कही गई है। हालांकि छात्रों का कहना है कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए।

युवाओं के भविष्य का सवाल

नीट देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक है, जिसमें लाखों छात्र डॉक्टर बनने के सपने के साथ शामिल होते हैं। ऐसे में परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखना शिक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

छात्रों का सवाल-मेहनत का हक कब मिलेगा?

कमल पवार सम्पादक जीत समाचार

आज की प्रमुख हस्ती

अमृता शेरगिलः भारतीय आधुनिक कला की महान चित्रकार, जिनकी कूची ने दुनिया में बनाई पहचान

भारतीय कला जगत में कुछ नाम ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और अनोखी शैली से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। उन्हीं महान कलाकारों में से एक थीं अमृता शेरगिल, जिन्हें भारत की सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक चित्रकारों में गिना जाता है। उनकी पेंटिंग्स में भारतीय जीवन, ग्रामीण संस्कृति, महिलाओं की भावनाएं और समाज की वास्तविक तस्वीर बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाई देती है।

अमृता शेरगिल ने कम उम्र में ही कला की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली थी। उनकी कला भारतीय परंपराओं और यूरोपीय चित्रकला शैली का अद्भुत संगम थी। यही कारण है कि उन्हें अक्सर ष्भारत की फ्रिदा काहलो भी कहा जाता है।

प्रारंभिक जीवन और कला की शुरुआत : अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को बुडापेस्ट (हंगरी) में हुआ था। उनके पिता उमराव सिंह शेरगिल एक विद्वान और संस्कृत के जानकार थे, जबकि उनकी माता मैरी एंटोनेट एक संगीत प्रेमी महिला थीं। बचपन से ही अमृता की रुचि चित्रकला और रचनात्मक कार्यों में थी।

उनका बचपन भारत और यूरोप दोनों जगहों की संस्कृतियों के बीच बीता। उन्होंने शुरुआती कला शिक्षा यूरोप में प्राप्त की और आगे चलकर पेरिस में प्रसिद्ध कला संस्थानों में अध्ययन किया। वहां उन्होंने पश्चिमी चित्रकला की बारीकियां सीखीं और अपनी कला को नई दिशा दी।

यूरोप से भारत तक का कलात्मक सफर : पेरिस में रहते हुए अमृता शेरगिल ने यूरोपीय शैली में कई चित्र बनाए और अपनी प्रतिभा के लिए पहचान हासिल की। वर्ष 1933 में उनकी एक पेंटिंग को पेरिस के प्रतिष्ठित कला मंच पर सम्मान मिला।

हालांकि, बाद में उनका मन भारतीय संस्कृति और जीवन की ओर आकर्षित हुआ। भारत लौटने के बाद उन्होंने गांवों, गरीब लोगों, महिलाओं और आम जीवन को अपनी कला का विषय बनाया।

उनकी पेंटिंग्स में भारतीय समाज की सच्चाई, भावनाएं और संघर्ष दिखाई देते हैं। उन्होंने सुंदरता को केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में देखा।

अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध पेंटिंग्स : अमृता शेरगिल की कई रचनाएं आज भी विश्वभर में प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रमुख पेंटिंग्स में शामिल हैं।

थ्री गर्ल्स,हिल वूमेन,ब्राइड्स टॉयलेट, यंग गर्ल्स, विलेज सीन ।

इन चित्रों में भारतीय महिलाओं, ग्रामीण जीवन और सामाजिक भावनाओं को बेहद गहराई से प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय महिलाओं की भावनाओं को दी आवाज : अमृता शेरगिल की कला की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने महिलाओं को केवल सुंदरता के प्रतीक के रूप में नहीं दिखाया, बल्कि उनके जीवन, अकेलेपन, संघर्ष और भावनाओं को भी चित्रों में स्थान दिया।

उनकी पेंटिंग्स में महिलाओं के चेहरे पर दिखाई देने वाली गंभीरता और भावनात्मक गहराई दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है।

कला में अनोखी शैली : अमृता शेरगिल की चित्रकला में चमकीले रंगों के बजाय गहरे और प्रभावशाली रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है। उनकी शैली में यूरोपीय तकनीक और भारतीय विषयों का सुंदर मेल था।

उन्होंने भारतीय कला को नई पहचान दी और आने वाली पीढ़ियों के कलाकारों के लिए एक नई दिशा तैयार की।

कम उम्र में निधन, लेकिन अमर विरासतः अमृता शेरगिल का निधन मात्र 28 वर्ष की आयु में 1941 में हुआ। इतनी कम उम्र में दुनिया छोड़ने के बावजूद उन्होंने भारतीय कला के इतिहास में ऐसा स्थान बनाया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

आज उनकी पेंटिंग्स भारत की राष्ट्रीय कला धरोहर का हिस्सा हैं। उनकी कई रचनाएं तज और अन्य प्रमुख कला संग्रहालयों में संरक्षित हैं।

अमृता शेरगिलः कला जगत की अमूल्य धरोहर : अमृता शेरगिल केवल एक चित्रकार नहीं थीं, बल्कि वह एक ऐसी कलाकार थीं जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से भारतीय समाज की आत्मा को दुनिया के सामने रखा। उनकी कूची ने भारतीय जीवन की सादगी, दर्द और सुंदरता को कैनवास पर उतारा।

भारतीय आधुनिक कला के इतिहास में अमृता शेरगिल का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उनकी कला आज भी कलाकारों और कला प्रेमियों को प्रेरणा देती है।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर (भारत)

1. आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (पुलिस, फायर, और एंबुलेंस)

112	आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (पुलिस, फायर, और एंबुलेंस)	104	स्वास्थ्य हेल्पलाइन (Health Helpline/Medical Advice)
100	पुलिस (Police)	1915	पर्यटन हेल्पलाइन (Tourist Helpline)
101	फायर ब्रिगेड (Fire Brigade)	1930	साइबर अपराध (Cyber Crime)
102 / 108	एम्बुलेंस सेवा (Ambulance)	139	रेलवे पूछताछ / सुरक्षा (Railway Enquiry / Security)
1091	महिला हेल्पलाइन (Women Helpline)	1363	पर्यटन हेल्पलाइन (Tourist Helpline)
1098	चाइल्ड हेल्पलाइन (Child Helpline)	1033	सड़क दुर्घटना या राष्ट्रीय राजमार्ग आपातकाल (Road Accident / National Highway Emergency)
		14567	बुजुर्ग हेल्पलाइन (Elder Line)
		1551	किसान कॉल सेंटर (Kisan Call Center)
		1906	गैस सिलेंडर (LPG) रिसाव या आपातकाल (LPG Gas Leak / Emergency)

2. राज्य / बिजली बोर्ड हेल्पलाइन नंबर (टोल-फ्री)

राज्य	हेल्पलाइन नंबर (टोल-फ्री)	वैकल्पिक संपर्क नंबर / वेबसाइट
हिमाचल प्रदेश (HPSEBL)	1912	1800-180-8060 | www.hpseb.in
उत्तर प्रदेश (UPPCL / अन्य)	1912	1800-180-8752 | www.uppcl.org
दिल्ली (BSES/TPDDL)	1912	वेबसाइट के माध्यम से चैटबॉट सपोर्ट www.bsesdelhi.com / www.tatapower-ddl.com
पंजाब (PSPCL)	1912	1800-180-1512 | www.pspcl.in
हरियाणा (DHBVN/UHBVN)	1912	1800-180-1833 | www.dhbvn.org.in / www.uhbvn.com
मध्य प्रदेश (MPPKVVCL)	1912	1800-233-1266, WhatsApp: 9425807257 www.mpez.co.in
उत्तराखंड (UPCL)	1912	1800-419-0405 | www.upcl.org

3. राज्यवार जल हेल्पलाइन नंबर

राज्य / विभाग	हेल्पलाइन नंबर	विवरण / वेबसाइट
केंद्रीय / राष्ट्रीय	1800-121-2164	जल जीवन मिशन का टोल-फ्री नंबर | www.jaljeevanmission.gov.in
हिमाचल प्रदेश (स्थानीय)	1800-180-8009, 1100	जल शक्ति विभाग (SNK), शिकायत निवारण केंद्र
दिल्ली	1916	दिल्ली जल बोर्ड (24x7) | www.delhijalboard.nic.in
उत्तर प्रदेश	1076	सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) | www.up.gov.in
बिहार	1800-123-1121	पीएचईडी (PHED) पेयजल शिकायत | www.prdbihar.gov.in
राजस्थान	1800-180-6088	जलदाय विभाग (PHED) | www.jalday.rajasthan.gov.in
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (सभी राज्य)	181 या 1902	सभी राज्यों की शिकायत और जानकारी के लिए

4. राज्यवार परिवहन (बस) हेल्पलाइन नंबर

राज्य / निगम	हेल्पलाइन नंबर	विवरण / उपयोग
हिमाचल प्रदेश (HRTC)	1100, 1800 180 8185	24/7 हेल्पलाइन, पूछताछ और शिकायत निवारण
दिल्ली (DTC)	011-22968836	आईएसबीटी (ISBT) पूछताछ
उत्तर प्रदेश (UPSRTC)	149, 1800 1800 151	24/7 टोल-फ्री सुविधा
राजस्थान (RSRTC)	181	मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता
चंडीगढ़ (CTU)	1800 274 7400	टोल फ्री नंबर

इन हेल्पलाइन नंबरों को सेव करें और जरूरत पड़ने पर उपयोग करें। यह आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

दैनिक समाचार पत्र
जीत समाचार
जीत सच्ची ख़बर की

मुद्रक, प्रकाशक व सम्पादक : कमल पवार द्वारा 11368, पवित्र नगर, वालिया कालोनी हैबोवाल कलां, लुधियाना से प्रकाशित एंव जीत लुधियाना प्रिंटर्स हैबोवाल लुधियाना से मुद्रित।

सम्पादक : कमल पवार इस अंक मे प्रकाशित एंव समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा उत्पन्न समस्त विवाद लुधियाना न्यायालय के अधीन होगे।

R.N.I NO. PUN/HIN/2013/60106

Contact us :- +91-98030-25111.

हरियाणा में पशुधन की नस्ल सुधार को मिलेगी रफ्तार, तरल नाइट्रोजन खरीद को मंजूरी

हरियाणा। हरियाणा सरकार ने राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुधन की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय खरीद समिति की बैठक में अगले दो वर्षों के लिए तरल नाइट्रोजन के दर अनुबंध को मंजूरी प्रदान की गई।

सरकार के इस निर्णय से उच्च गुणवत्ता वाले फ्रोजन सीमन का सुरक्षित संरक्षण सुनिश्चित होगा, जिससे राज्य में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमों को और गति मिलेगी। इसके माध्यम से पशुपालकों को बेहतर आनुवंशिक क्षमता वाले पशुधन उपलब्ध होंगे, जिससे दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

बैठक में बताया गया कि पशुधन की नस्ल सुधार योजना को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। तरल नाइट्रोजन की उपलब्धता से फ्रोजन सीमन की गुणवत्ता लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी और राज्यभर में चल रहे कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकेंगे।

सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि हरियाणा के डेयरी क्षेत्र को भी नई मजबूती मिलेगी और राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले पशुधन के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

करनाल स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा, समय पर काम पूरा न करने वाली एजेंसियों पर होगी सख्त कार्रवाई

जीत समाचार ब्यूरों करनाल। करनाल के उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।

उपायुक्त ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से कार्यों की निगरानी करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो निर्माण एजेंसियां तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा नहीं करेंगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसलिए सभी कार्य गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं, ताकि आम जनता को इन योजनाओं का लाभ शीघ्र मिल सके।

पिंजौर से 'वन चेतना यात्रा-2026' का शुभारंभ, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

जीत समाचार पिंजौर/पंचकूला। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को जनआंदोलन बनाने के उद्देश्य से पिंजौर से 'वन चेतना यात्रा-2026' का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया तथा हरित धरा के संकल्प के साथ पौधारोपण भी किया गया।

कार्यक्रम के दौरान लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की गई कि वे वृक्षारोपण अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लें और हरियाणा को हरित, स्वच्छ एवं समृद्ध बनाने में अपना योगदान दें। साथ ही यह संदेश भी दिया गया कि लगाए गए पौधों का संरक्षण और देखभाल करना उतना ही आवश्यक है जितना उनका रोपण।

'वन चेतना यात्रा-2026' का उद्देश्य राज्यभर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना, हरियाली को प्रोत्साहित करना तथा अधिक से अधिक लोगों को वृक्षारोपण अभियान से जोड़ना है।

नारनौल के ऐतिहासिक जल महल का डीसी अनुपमा अंजली ने किया औचक निरीक्षण, जल्द पानी भरवाने के निर्देश

जीत समाचार ब्यूरों, नारनौल। नारनौल की उपायुक्त अनुपमा अंजली ने सोमवार को ऐतिहासिक जल महल का औचक निरीक्षण कर वहां चल रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल महल के सौंदर्यकरण, रखरखाव और संरक्षण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उपायुक्त ने सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता (एसई) अमित कुमार रघुवंशी को प्राथमिकता के आधार पर जल महल में शीघ्र पानी भरवाने के निर्देश दिए, ताकि इस ऐतिहासिक धरोहर का प्राकृतिक और पारंपरिक स्वरूप पुनः स्थापित किया जा सके।

उन्होंने पूरे परिसर में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया। डीसी ने कहा कि जल महल जिले की ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके संरक्षण एवं विकास के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।

उपायुक्त अनुपमा अंजली ने कहा कि नारनौल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हरियाणा सरकार का उद्देश्य जल महल जैसे ऐतिहासिक स्थलों का विकास कर पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिससे जिले की पहचान मजबूत होने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त तरुण कुमार पावरिया, एसडीएम नारनौल अनिरुद्ध यादव तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

बठिंडा में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य, 2025 में 4,335 आवारा कुत्तों का हुआ टीकाकरण व नसबंदी

जीत समाचार ब्यूरों बठिंडा । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत बठिंडा नगर निगम ने शहर में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। नागरिकों को इस संबंध में जागरूक करने के लिए नगर निगम द्वारा विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही, आवारा कुत्तों के सुरक्षित एवं मानवीय प्रबंधन को लेकर भी लोगों को जानकारी दी जा रही है।

नगर निगम आयुक्त लवजीत कालसी ने बताया कि अब पालतू कुत्तों का पंजीकरण घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल और उैमूं ऐप के माध्यम से आसानी से कराया जा सकता है। पंजीकरण के लिए मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, पता, कुत्ते की फोटो, नस्ल, आयु तथा टीकाकरण संबंधी जानकारी देना आवश्यक होगा।

अहनलाइन सुविधा के अलावा नगर निगम कार्यालय, माल गोदाम रोड स्थित कमरा नंबर-27 में भी पंजीकरण कराया जा सकता है। लोगों को जागरूक करने के लिए नगर निगम की टीमें स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और विभिन्न इलाकों में जाकर जानकारी दे रही हैं तथा पालतू पशु मालिकों को सभी नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

2025 में 4,335 आवारा कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी

नगर निगम द्वारा महाराजा रणजीत सिंह विश्वविद्यालय के निकट डबवाली रोड स्थित पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में आवारा कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। वर्ष 2025 के दौरान कुल 4,335 आवारा कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी की गई, जिनमें 2,125 नर तथा 2,210 मादा कुत्ते शामिल हैं।

शिकायत और सहायता के लिए हेल्पलाइन जारी

नगर निगम ने आवारा कुत्तों से संबंधित शिकायतों, कुत्तों के आक्रामक व्यवहार, टीकाकरण, नसबंदी तथा पालतू कुत्तों के पंजीकरण संबंधी सहायता के लिए मुख्य स्वच्छता निरीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए नागरिक 94788-40058 पर संपर्क कर सकते हैं।

नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने पालतू कुत्तों का समय पर पंजीकरण कराएं, पशु कल्याण संबंधी नियमों का पालन करें और आवारा पशुओं के प्रति संवेदनशील एवं मानवीय व्यवहार अपनाएं।

समूह समाज संगठन (ससस) रजि.
SSS

बेसहारा गऊ अते पशुआं दी संभाल
ISO 9001:2015
ISO मानता प्राप्त पड़ाई

रुज़गार काउंसलिंग

वेसट अते पलासटिक रिसाइकलिंग
बॅचे, औरतां अते बज़ुरगां दे समाजिक विकास विॅच सहिजोग दिउ
वारड वलंटीअर पुआइंट
संपरक : 85679-57745, 90410-90470

दैनिक समाचार पत्र
जीत समाचार
जीत सच्ची खबर की
अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें newseditor.jeetsamachar@gmail.com पर ई-मेल करें। खबर और विज्ञापन देने के लिए सम्पर्क करें : 9803025111, 8878400009, 9803589008.

एफ-सीसी कमेटी में दो एमएलए बेटों की नियुक्ति पर घमासान

कांग्रेस पार्षद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे एफिडेविट, नियुक्तियों को बताया गैर-संवैधानिक

जीत समाचार लुधियाना(कमल पवार)। लुधियाना नगर निगम की फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कमेटी में दो सदस्यों की नियुक्ति को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने नेता विपक्ष शाम सुंदर मल्होत्रा की अगुवाई में एक अहम बैठक कर इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाई और कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया।

बैठक के दौरान सभी कांग्रेस पार्षदों ने निर्णय लिया कि वे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अपने-अपने एफिडेविट दाखिल करेंगे। इन एफिडेविट में यह स्पष्ट किया जाएगा कि फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्सकमेटी में की गई दो सदस्यों की नियुक्ति कथित तौर पर गैर-संवैधानिक है और उन्हें चुनावी एवं वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया गया।

पहले ही हाई कोर्ट पहुंच चुका है मामला : गौरतलब है कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्षद गौरव भट्टी पहले ही पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। अब कांग्रेस के सभी पार्षद इस मामले में एकजुट होकर 27 जुलाई को अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे।

कांग्रेस का आरोप : कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी महत्वपूर्ण कमेटी में नियुक्तियां लोकतांत्रिक प्रक्रिया और पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत होनी चाहिए।

उनका आरोप है कि:

- दो सदस्यों की नियुक्ति बिना उचित चुनाव प्रक्रिया के की गई।
- पार्षदों को वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया गया।
- इससे नगर निगम की कार्यप्रणाली की पारदर्शिता और वैधानिकता पर सवाल खड़े हुए हैं।

क्या है कांग्रेस की मांग? : कांग्रेस पार्षदों ने मांग की है कि कथित गैर-संवैधानिक नियुक्तियों को तुरंत रद्द किया जाए और फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कमेटी के सदस्यों का चुनाव पंजाब म्युनिसिपल कहर्पोरेशन एक्ट के तहत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार कराया जाए।

पार्षदों का कहना है कि इससे नगर निगम की कार्यवाही अधिक पारदर्शी, कानूनी और जवाबदेह बन सकेगी।

बैठक में शामिल रहे ये पार्षद : बैठक में नेता विपक्ष शाम सुंदर मल्होत्रा के अलावा हरजिंदर पाल लाली, गौरव भट्टी, पंकज काका, मोनू खिंडा, जसविंदर बीरू, हरविंदर कलेर, सोनू डिक्कू, स्वर्णदीप चहल, कमलजीत बोपा राय, भूपिंदर कौर गोपी, निर्मल कैरा, दिलराज सिंह, परमिंदर कौर इंडी, महाराज राजी, सुखदेव बावा, शालू डावर, विक्की और अन्य कांग्रेसी पार्षद मौजूद रहे।

जीत समाचार की बात: फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कमेटी नगर निगम की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि वित्तीय और ठेकों से जुड़े बड़े फैसले इसी कमेटी के माध्यम से लिए जाते हैं। ऐसे में यदि इसकी संरचना और नियुक्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो इसका असर सीधे नगर निगम की वैधता और पारदर्शिता पर पड़ सकता है।

अब सबकी नजरें 27 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह साफ हो सकेगा कि यह मामला केवल सियासी विवाद है या फिर वास्तव में नियुक्ति प्रक्रिया में कानूनी खामियां हैं।

ठियोग में एडीजे कोर्ट स्थापित करने के लिए गंभीर प्रयास होंगे: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर

जीत समाचार ब्यूरों ठियोग/शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि ठियोग में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट स्थापित करने की मांग पूरी तरह जायज है और इस दिशा में सरकार गंभीरता से प्रयास करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस विषय को मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा तथा विधि विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर एडीजे कोर्ट शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा।

रोहित ठाकुर मंगलवार को जिला शिमला के ठियोग प्रवास के दौरान ठियोग बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ और युवा अधिवक्ताओं के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं और मांगों को सुना।

डिजिटल न्याय व्यवस्था पर दिया जोर : शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय डिजिटल तकनीक का है और न्यायिक व्यवस्था को भी तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि न्यायालयों में डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के लिए योजना तैयार कर आवश्यक बजट की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कोटखाई सब-जज कोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र की न्यायिक व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी।

खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए ₹1 लाख की घोषणा : कार्यक्रम के दौरान रोहित ठाकुर ने अपनी ऐच्छिक निधि से खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए ₹1 लाख देने की घोषणा भी की।

ठियोग को मिले चार सीबीएसई स्कूल : शिक्षा मंत्री ने कहा कि ठियोग जिला शिमला का प्रवेश द्वार है और यहां के विद्यार्थियों ने शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि ठियोग विधानसभा क्षेत्र को चार सीबीएसई आधारित विद्यालय प्रदान किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा।

स्थानीय विधायक ने जताया आभार : कार्यक्रम में ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने क्षेत्र को चार सीबीएसई स्कूल उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्वयं अधिवक्ता होने के कारण वह बार एसोसिएशन की समस्याओं को भली-भांति समझते हैं और शिक्षा मंत्री से उनकी मांगों पर सकारात्मक एवं सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया।

इस अवसर पर बार एसोसिएशन ठियोग के अध्यक्ष भूपेंद्र कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता मदन ठाकुर, किशन ठाकुर, मदन चौहान, ज्ञान चंदेल सहित बार एसोसिएशन के सदस्य एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

करसोग में मानसून को लेकर प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील क्षेत्रों में मशीनरी तैनात करने के निर्देश

जीत समाचार करसोग (मंडी)। मानसून सीजन के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए करसोग उपमंडल प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपमंडलाधिकारी अलीशा चौहान की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा मानसून को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

बैठक में एसडीएम ने कहा कि पिछले वर्ष मानसून के दौरान सामने आई चुनौतियों से सीख लेते हुए इस बार पहले से बेहतर तैयारियां सुनिश्चित की जाएं, ताकि आपदा की स्थिति में जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में मशीनरी रखने के निर्देश : एसडीएम अलीशा चौहान ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि संवेदनशील और भूस्खलन संभावित स्थानों पर आवश्यक मशीनरी पहले से तैनात रखी जाए, ताकि सड़क बंद होने की स्थिति में तुरंत बहाली कार्य शुरू किया जा सके।

उन्होंने विशेष रूप से सेब उत्पादक क्षेत्रों की सड़कों की नियमित निगरानी करने और यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

कुट्टी और पुराने बाजार क्षेत्र में पार्किंग पर रोक: बैठक में पिछले वर्ष सरकोल नाला में बादल फटने की घटना का उल्लेख करते हुए एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात के दौरान कुट्टी और पुराने बाजार क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग न होने दी जाए।

उन्होंने कहा कि खतरे वाले चिन्हित स्थानों पर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर उन्हें समय रहते सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था तैयार रखी जाए।

राहत शिविरों में सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश : एसडीएम ने कहा कि आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों के ठहरने के लिए चिन्हित स्थानों पर भोजन, पेयजल, बिजली, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाएं पहले से उपलब्ध कराई जाएं।

उन्होंने बताया कि एसडीएम कार्यालय परिसर में जल्द ही हूटर स्थापित किया जाएगा, जिसका उपयोग आपदा या संभावित खतरे की स्थिति में लोगों को समय रहते सतर्क करने के लिए किया जाएगा।

हर विभाग नियुक्त करे नोडल अधिकारी : अलीशा चौहान ने सभी विभागाध्यक्षों को मानसून अवधि के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए, ताकि आपदा से जुड़ी सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान और बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने आम जनता से अपील की कि बरसात के मौसम में प्राकृतिक जल स्रोतों का पानी उबालकर ही पीने के लिए इस्तेमाल करें और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा एडवाइजरी का पालन करें।

बैठक में डीएसपी चांद किशोर, तहसीलदार पृथी चंद, नायब तहसीलदार राहुल शर्मा, बीएमओ डॉ. गोपाल चौहान, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अजय राज गुप्ता, जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता बुद्धि सिंह, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता चंद्रमणि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

दिल्ली लाठीचार्ज के विरोध में हिमाचल कांग्रेस का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री सुक्खू और उपमुख्यमंत्री अग्निहोत्री रहे शामिल

जीत समाचार शिमला। नई दिल्ली में युवाओं पर हुए कथित लाठीचार्ज तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में मंगलवार को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने शिमला स्थित लोक भवन के बाहर धरना-प्रदर्शन किया।

इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, कांग्रेस विधायक, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

धरने के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने तथा युवाओं की न्यायोचित मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने का आग्रह किया।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती संवाद, जनविश्वास और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति में निहित होती है। उनका आरोप था कि छात्रों और युवाओं की आवाज सुनने के बजाय उनके खिलाफ बल प्रयोग किया गया, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर युवाओं के मुद्दों पर संवाद और लोकतांत्रिक समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से युवाओं की मांगों पर सकारात्मक पहल करने और लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करने की अपील की।

कांगड़ा के शाहपुर में बादल फटने से भारी तबाही, 6 मकान बहेय राहत कार्य में जुटा प्रशासन

जीत समाचार कांगड़ा । हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मानसूनी बारिश के बीच जिला कांगड़ा के शाहपुर उपमंडल की बोह घाटी में मंगलवार को बादल फटने के बाद आई अचानक बाढ़ और मलबे ने भारी तबाही मचा दी। स्पैडा और गढ़गून गांव सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जहां तेज बहाव की चपेट में आकर छह मकान पूरी तरह बह गए, जबकि कई अन्य भवनों और गौशालाओं को भी नुकसान पहुंचा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, पहाड़ी क्षेत्र में अचानक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद भारी मात्रा में पानी और मलबा तेजी से नीचे की ओर आया। देखते ही देखते मलबे ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि ग्रामीणों ने समय रहते घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने में सफलता हासिल की, जिससे अब तक किसी जानी नुकसान की सूचना नहीं है।

भूस्खलन से राहत कार्य प्रभावित : घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिए गए। प्रभावित क्षेत्र में एसडीआरएफ की टीम को भी रवाना किया गया है। हालांकि, लगातार बारिश और डिब्बा तथा मानेड नाला क्षेत्र में हुए भारी भूस्खलन के कारण सड़कें बाधित हो गई हैं, जिससे राहत दलों को प्रभावित गांवों तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

एसडीएम शाहपुर ने की सतर्क रहने की अपील : एसडीएम शाहपुर डॉ. गणेश ठाकुर ने बताया कि वे स्वयं प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना हो चुके हैं और प्रशासन पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव कार्य प्राथमिकता के आधार पर चलाए जा रहे हैं।

उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लगातार बारिश के कारण नदी-नालों में जलस्तर और बहाव बेहद तेज है। ऐसे में लोग नदी-नालों के किनारे जाने से बचें और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें।

नुकसान का आकलन जारी : प्रशासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का विस्तृत आकलन कर रही हैं। वहीं, मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी किए जाने के बाद लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। प्रभावित परिवारों को हरसंभव राहत और सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है।

लाख रुपये की लागत से बना वातानुकूलित सम्मेलन कक्ष, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं।

जीत समाचार ऊना। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, ऊना में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उपायुक्त जतिन लाल ने मंगलवार को लगभग 10 लाख रुपये की लागत से निर्मित आधुनिक वातानुकूलित सम्मेलन कक्ष का लोकार्पण किया।

करीब 60 लोगों की क्षमता वाले इस सम्मेलन कक्ष का उपयोग पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठकों, विचार-विमर्श, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों के लिए किया जाएगा।

लोकार्पण के अवसर पर उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि जिला प्रशासन सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों को सम्मानजनक एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य सभी आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है, ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उन्होंने बताया कि घनारी में ईसीएचएस पहलीक्लिनिक पहले से संचालित है, जबकि रोड़ा में लगभग 4.5 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सैनिक भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके बनने के बाद सैनिकों और पूर्व सैनिकों को विभिन्न सेवाएं एवं सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हो सकेंगी। उपायुक्त ने यह भी जानकारी दी कि कार्यालय परिसर में 3.5 लाख रुपये की लागत से पार्किंग सुविधा का विस्तार किया गया है। उन्होंने परिसर स्थित लीगल सर्विस क्लीनिक का निरीक्षण भी किया और उसकी छत की शीघ्र मरम्मत के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय के उप निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल एस.के. कलिया ने बताया कि कार्यालय के माध्यम से पूर्व सैनिकों को पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान, मेडिकल सहायता, सीएसडी सुविधाएं तथा अन्य आवश्यक सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विभाग समय-समय पर दूरदराज के क्षेत्रों में जागरूकता शिविर आयोजित कर सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार कार्य कर रहा है।

कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्नल रघुवीर सिंह, कृष्ण पाल चन्झोत्रा, के.सी. शर्मा, सेवानिवृत्त सैनिक लीग के अध्यक्ष कैप्टन शक्ति चंद, बीडीओ राहुल धीमान सहित अनेक पूर्व सैनिक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

जीत समाचार TV
जीत सच्ची खबर की
जीत समाचार को हर जिले, शहर आदि से रिपोर्ट की आवश्यकता है। यदि आप में है दम तो मौका देगे हम!
जीत समाचार आपकी तीसरी आँख बन कर आपका मार्गदर्शन करेगा। आप के शहर मे कोई ऐसी खबर हो तो आप हमारी अखबार व टीवी में दिखाना चाहते है तो सम्पर्क करे।
9041090470

छात्रों पर लाठीचार्ज से भड़के अरिजीत सिंह, बोले- 'खुद को भगवान समझ लिया है क्या?'

राजधानी दिल्ली में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में आयोजित संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस घटना पर अब बॉलीवुड के लोकप्रिय गायक अरिजीत सिंह ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए।

अरिजीत सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा, : 'यार, अब तो स्टूडेंट्स को मार रहे हैं आप लोग। आपको शर्म नहीं आती? हैलो नेता, मंत्री... क्या चल रहा है भाई? अपने आपको भगवान समझ लिया है क्या? हर चीज याद रखी जाएगी। हर-हर महादेव। याद रखना, बदलाव ही एकमात्र सच्चाई है।'

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि 'अभी यूनिफहर्म में ऐसे लोगों के वीडियो देख रहा था, जो गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे थे।'

सोनम वांगचुक के समर्थन में भी आए थे सामने : यह पहली बार नहीं है जब अरिजीत सिंह ने किसी सामाजिक मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी हो। इससे पहले 15 जुलाई को उन्होंने जंतर-मंतर पर भूख

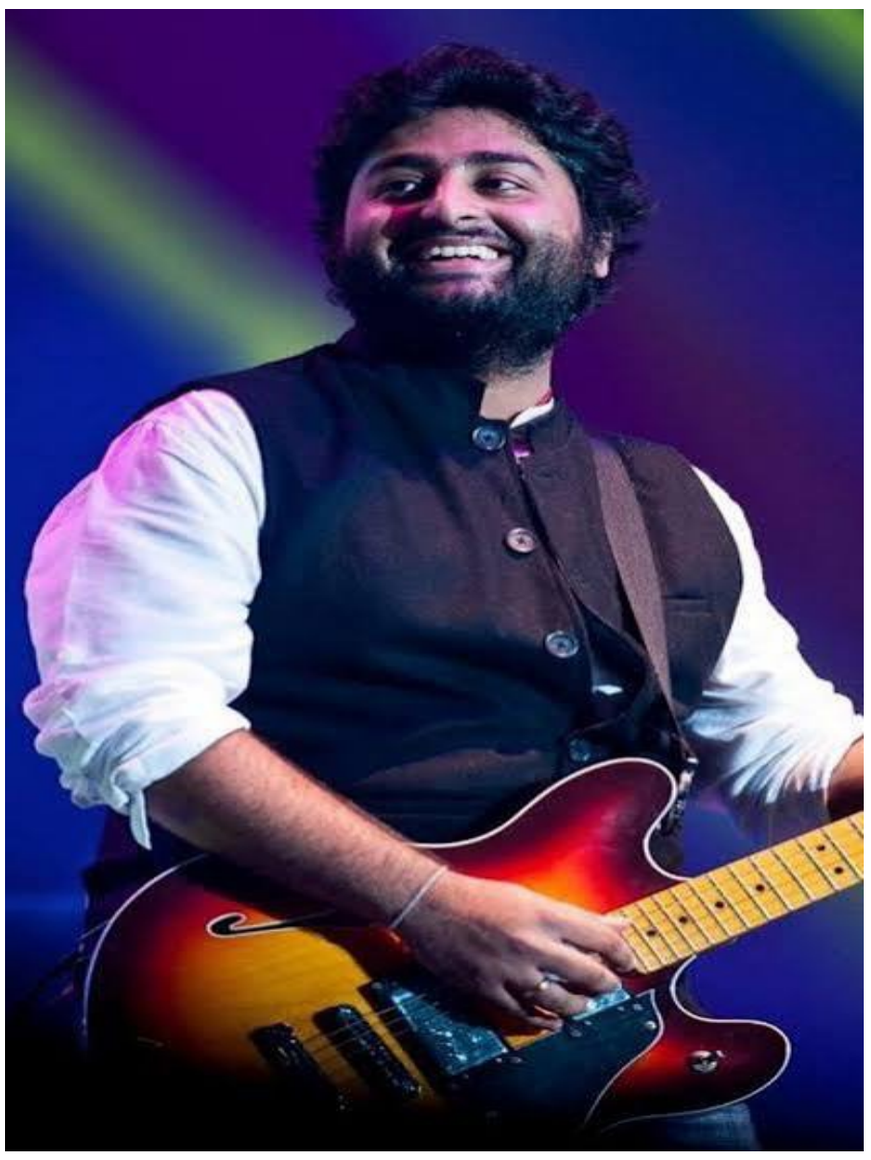

हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के समर्थन में पोस्ट करते हुए लिखा था, 'आपके लिए प्यार और दुआएं वांगचुक सर। भगवान आपको ताकत दें।'

रिटायरमेंट के बाद फिर सुर्खियों में : कुछ समय पहले अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाने की घोषणा की थी। हालांकि उन्होंने पहले से किए गए प्रोजेक्ट पूरे करने की बात कही थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि वह एक बार फिर संगीत की दुनिया में सक्रिय हो गए हैं। उनकी आवाज में फिल्म 'आवारापन 2' का नया गीत 'ये आवारापन' रिलीज हो चुका है। इस गीत का संगीत अमाल मलिक ने तैयार किया है, जबकि इसके बोल रश्मि-विराग ने लिखे हैं।

मामला क्यों गरमाया? : दिल्ली में संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस घटना के बाद राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और फिल्मी हस्तियों की प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। अरिजीत सिंह का बयान भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

छात्रों के समर्थन में बोले दिलजीत दोसांझ, कहा 'फिर मुझे एंटी-नेशनल कहा जाएगा'

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर जारी विवाद के बीच पंजाबी गायक एवं अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर छात्रों के समर्थन में एक संदेश साझा करते हुए प्रशासन से प्रदर्शनकारियों की मांगों को सुनने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के बाद उन्हें फिर से 'एंटी-नेशनल' कहे जाने की आशंका है।

क्या कहा दिलजीत दोसांझ ने? : दिलजीत दोसांझ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि छात्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, वह उचित नहीं था। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि छात्रों की मांगों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि 'आज जो कुछ भी हुआ, वह बहुत गलत था। छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि वे छात्रों की मांगों को सुनें। जनता की आवाज ही भगवान की आवाज होती है।'

फिर एंटी-नेशनल कहा जाएगा : दिलजीत ने आगे लिखा कि सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी राय रखने के कारण उन्हें पहले भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि

उस समय भी उन्हें ष्देशद्रोहीष और 'एंटी-नेशनल'कहा गया था।

उनके अनुसार, मुझे पहले भी कई बार देशद्रोही कहा जा चुका है। अब शायद फिर मुझे एंटी-नेशनल कहा जाएगा। किसान आंदोलन के बाद मैंने काफी विरोध और कई कानूनी परेशानियों का सामना किया, जिनके बारे में मैं बात भी नहीं कर सकता। लेकिन भगवान सब देख रहा है।

क्या है पूरा मामला? : दिल्ली में हाल के दिनों में विभिन्न छात्र संगठनों और प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों और शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की घटनाएं सामने आईं, जिनमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की भी खबरें आईं।

इस मुद्दे पर कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और फिल्मी हस्तियों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अभिनेता शबाना आजमी और प्रकाश राज भी प्रदर्शन के दौरान छात्रों के समर्थन में मौजूद रहे।

सोशल मीडिया पर तेज हुई बहस : दिलजीत दोसांझ के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। एक वर्ग उनके बयान का समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा वर्ग उनकी टिप्पणी की आलोचना कर रहा है। फिलहाल, उनके बयान पर सरकार या संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।